

[1]

IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
AT JAIPUR BENCH, JAIPUR

O R D E R

S.B. CIVIL WRIT PETITION NO. 964/2001

MRS. KRISHNA GUPTA & ANR.
Vs.
RAJASTHAN HOUSING BOARD & ORS.

DATE: 24.07.2007

HON'BLE MR. JUSTICE K.S. RATHORE

Mr. Shailesh P. Sharma for the petitioners.
Mr. Virendra Lodha for the respondents.

The short controversy in this writ petition is that the petitioners were allotted a house No. 1-B-21 and after registration, possession was handed over to the petitioners and this allotment was made pursuant to the order passed by this Court in the earlier writ petition filed by the petitioners.

The petitioners raised grievance that higher rates have been charged from them and the same has been examined by the Grievance Committee and vide order dated 27.05.2000 after considering each and every aspect, the Grievance Committee has observed as under:-

"इस संबंध में उप-आवासन आयुक्त कोटा से समझौता समिति के समस्त सदस्यों द्वारा विस्तार से विचार विमर्श किया गया एवं चर्चा के दौरान यह तथ्य सामने आये कि प्रार्थी को उक्त

आवास एस एफ एस योजना के तहत मण्डल की संपत्ति आंवटन समिति की बैठक दिनांक 14-6-96 को आवंटित किया गया था। प्रार्थी अपने आवास की तुलना जिन अन्य आंवटियों को आवंटित आवासों से कर रहा है, वह उचित नहीं है। चूंकि अन्य आवास जिनके सम्बन्ध में आवंटी ने अवगत कराया है, जैसे कि 5-बी-42 आदि, ये आवास नकद भुगतान पद्धति पर आवंटितों से किश्तें जमा कराने के पश्चात् ही आवंटित किये गये थे जबकि आंवटियों से आवास निर्माण के दौरान कोई भी राशि आवास के पेटे वसूल नहीं की जाती है अतः दोनों प्रकार की आवासों की कीमत में अन्तर होना स्वाभाविक है। इसके अतिरिक्त प्रार्थी ने कब्जा लेते समय इस तरह के कोई भी विराध मण्डल के समक्ष प्रस्तुत नहीं किये थे कि उक्त आवास की कीमत अधिक है या आवास निर्माण में कोई कमियां हैं। प्रार्थी ने आवास का कब्जा लेने के पश्चात् समस्त राशि जमा कराकर आवास का रजिस्ट्रेशन भी अपने पक्ष में करा लिया है। अतः अब इस स्तर पर करीब तीन वर्ष बाद प्रार्थी के द्वारा चाहे गये अनुतोष पर विचार किया जाना एवं समझौते के द्वारा प्रकरण को निर्णित किया जाना सम्भव नहीं है।"

Having heard rival submissions of the respective parties and upon careful perusal of the impugned order dated 27.05.2000, I find no illegality in the impugned order and the same requires no interference whatsoever by this Court.

Consequently, the writ petition fails and the same is dismissed.

(K. S. RATHORE), J.